Need for Removal of Railway Track from Jodhpur to Fidusar in Rajasthan

डा॰ नारायण सिंह मानकलाव (नाम निर्देशित) : उपसभापति महोदय, ज्यादातर सदस्य रेलवे लाइन बिछाने की बात करते हैं, मैं रेलवे लाइन उखाड़ने की बात कर रहा हूं।

महोदय, उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डिवीजन में एक मीटर गेज की रेलवे लाइन का आजादी से पूर्व भगत की कोठी से सूरसागर तक जोधपुर रेलवे द्वारा छीत्तर के सफेद सैण्ड स्टोन की ढुलाई के लिए निर्माण किया गया था। उस समय यह लाइन शहर के बहुत ही बाहरी क्षेत्र से निकाली गई थी, जिस पर उस समय पत्थर की ढुलाई नियमित रूप से हुआ करती थी। परन्तु विगत 30 वर्षों से इस रेलवे लाइन पर कोई लदान नहीं होने के कारण रेल विभाग द्वारा बीच-बीच में कई जगह से रेलवे लाइन को हटा लिया गया है, तो भी कई जगहों से पटरियां चोरी हो रही हैं। चूंकि अब यह रेलवे लाइन शहर के बहुत ही व्यस्त क्षेत्र से निकल रही है, इसलिए यह बेकार पड़ी रेलवे लाइन कई समस्याएं पैदा कर रही है।

अत: मेरा आग्रह है कि रेलवे लाइन के इस भाग को उखाड़कर रेलवे एवम् जन साधारण को होने वाली हानि से मुक्ति प्रदान करें।

Need to Regularise the Services of Border Home Guards in Rajasthan

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान) : परम सम्माननीय उपसभापति महोदय, मेरा विशेष उल्लेख बॉर्डर होम गार्ड के जवानों को सेवा में स्थाई स्थान देने के संबंध है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके द्वारा मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि बॉर्डर होम गार्डों की राजस्थान में चार बटालियन हैं। राजस्थान के सीमा क्षेत्र में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा श्री गंगानगर जिले हैं। बॉर्डर होम गार्डों का गठन वहीं पर किया गया है जहां अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र लगता है। एक बटालियन में छ: कम्पनी होती हैं। एक बटालियन में 666 स्वयं सेवक होते हैं।

राजस्थान में बॉर्डर होम गार्डों के 2664 स्वयं सेवक हैं, जिनका भविष्य अन्धकार में है। बॉर्डर होम गार्ड, स्वयं सेवक के रूप में स्थानीय नागरिकों को शारीरिक व शैक्षणिक मापदंड के योग्य होनहार युवकों की भर्ती किया जाता है तथा भर्ती के उपरांत उन्हें कठिन से कठिन कार्य दिया जाता है और प्रशिक्षण दिलाया जाता है, लेकिन न ही उन्हें बराबर कार्य करने की ड्यूटी मिलती है और न ही उनकी कोई सुध ली जाती है, जबकि 75% राशि केन्द्र सरकार वहन करती है और 25% राशि राज्य सरकार वहन करती है। राज्य सरकार को तो फायदा है कि उन्हें थोड़ी राशि देनी पड़ती है। अत: इन जवानों को सेवा में स्थाई स्थान देने की आवश्यकता है।

श्री उपसभापति: इसे निकाल दीजिए। जो आप बोल रहीं हैं, यह तो आपके टैक्स्ट में नहीं है।

Need to stop misuse of VIP/VVIP Residential Premises in Delhi

SHRI S. P. M. SYED KHAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman Sir. My Special Mention is regarding the request to stop misuse of VIP/VVIP residential premises in Delhi.

Sir, there is no doubt that the residential areas of VIP/VVIPs in Delhi are well-maintained, with good ambience and beautiful lawns, by the civic authorities, namely, NDMC and CPWD. But, at the same time, it is noticed in the North Avenue that several functions are taking place, almost everyday, with tents and loudspeakers, which are, to my knowledge, not concerned with any MPs or VIPs. The lawns in the North Avenue are used for the purpose of holding such functions, including marriages by strangers. This kind of commercial activity in the North Avenue is considered to be serious, taking into account the security cover to the VIPs. The left-outs after the functions are over, remain unclean, result in in bad smell. This would lead to health hazards to the public. The noise pollution arising out of the use of loudspeakers is also a nuisance there.

In the circumstances, I would urge upon the Government to look into the matter and take necessary steps so as not to allow persons other than the occupants of the VIP areas to hold any functions, there in order to provide a better environment for the VIP/VVIPs.

SHRI N. R. GOVINDRAJAR (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the Special Mention.

Permission to install a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Meghdambri, Raigad Fort

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र) : महोदय, महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित, रायगढ़ किला एक संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन है, इसलिए वहां पर कोई भी कार्य करने के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार रायगढ़ किले में, मेघडंबरी में, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करना चाहती है और इसके लिए उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को वर्ष 2003 में पत्र लिखा था। इसके बाद वर्ष 2004 में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने स्वयं केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री तथा प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखे थे, परन्तु अभी भी वह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ा हुआ है और केन्द्रीय सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में अनुमति प्रदान नहीं की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि रायगढ़ किले में मेघडंबरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को तुरन्त अनुमति प्रदान की जाये। यह मामला केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए दो वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है।

Demand for release of adequate assistance from National Calamity Contingency fund and foodgrains for drought affected areas of Karnataka

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, my home State, Karnataka, was reeling under severe drought conditions for the last few